प्रेस विज्ञप्ति

29 फरवरी, 2016

केंद्रीय बजट 2016–17 की आलोचना

1. किसानों की हिमायत करने वाले श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज बजट के दिन ही डीजल की कीमत रु. 1.47 पैसे बढ़ाकर किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है। डीजल वो ईंधन है, जो किसानों के लिए सबसे अधिक काम आता है, चाहे सिंचाई के लिए पंपिंग सेट हो या फिर ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हो। केंद्रीय बजट 2016–17 'देश में महंगाई बढ़ाने वाला बजट' है, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग एवं वेतनभोगियों/कर्मचारियों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल देगा। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध हो जाता है :–

   (i) लोगों के लिए निर्धारित टैक्स स्लैब्स में आम आदमी को टैक्स में कोई राहत नहीं।

   (ii) सेवा कर, 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। मोदी सरकार ने 22 महीनों में सेवाकर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इतने छोटे समय में 3 प्रतिशत की वृद्धि बहुत बड़ी है। इससे सभी सेवाएं अधिक महंगी हो जाएंगी, एवं आम उपभोक्ता पर महंगाई का अधिक बोझ बढ़ेगा।

   (iii) 1000 रु. या इससे अधिक मूल्य के 'रेडीमेड गारमेंट्स' युवाओं एवं आम उपभोक्ताओं पर अधिक भार डालेंगे।

   (iv) यहां तक कि 'इमिटेशन ज्वेलरी' एवं 'सिल्वर ज्वेलरी' भी अतिरिक्त टैक्सभार के कारण अधिक महंगी हो जाएगी। देश के युवा रेडीमेड गारमेंट्स एवं ज्वेलरी के टैक्सेशन से सीधे प्रभावित होंगे।

   (v) छोटी कारों/एलपीजी वाहनों पर '1 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर कर', सार्वजनिक परिवहन जैसे बस/ट्रक/कमर्शियल वाहनों आदि सहित डीजल वाहनों पर 2 प्रतिशत उपकर आम नागरिकों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालेगा।

   (vi) मोनो रेल/मेट्रो पर 5.6 प्रतिशत कर एवं ट्रैमवे पर 14 प्रतिशत नए कर से आम यात्रियों की जेब पर अब अधिक भार पड़ेगा।

   (vii) 'स्टेज कैरेज पर्मिट' मतलब प्रायवेट ऑपरेटर्स द्वारा बसों के संचालन पर नया 5.6 प्रतिशत कर लगाए जाने से आम यात्रियों की यात्रा महंगी हो जाएगी।

   (viii) कोयले, लिग्नाईट आदि पर बढ़े हुए कर से आम लोगों को बिजली के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा।

   (ix) एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों जैसे 'वॉईस ओवर

इंटरनेट प्रोटोकॉल ईक्विपमेंट', 'मॉडम', 'इंटरनेट प्रोटोकॉल रेडियो स्विचेस' आदि पर 10 प्रतिशत (पहले 0 प्रतिशत) का नया टैक्स लगा दिया।

(x) प्राईमरी एलुमिनियम पर कर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत एवं एलुमिनियम उत्पादों पर कर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। एलुमिनियम एवं इसके उत्पादों का प्रयोग अक्सर समाज के गरीब वर्ग के लोग करते हैं।

(xi) एक तरफ सरकार 'रिन्यूएबल ऊर्जा' को बढ़ावा देती है, लेकिन बजट में 'सोलर वाटर हीटर्स' पर कर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत एवं 'सोलर टैम्पर्ड ग्लास' पर कर 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

(xii) गरीब एवं आम कर्मचारियों की मेहनत की कमाई पर कर लगाए जाने के बाद मैच्योरिटी के समय 'कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड' एवं 'पब्लिक प्रॉविडेंट फंड' पर कर दिए जाने के चलते बचत कम हो जाएगी।

2. अमीर एवं गरीब के बीच असमानता बढ़ रही है। 'अप्रत्यक्ष कर' हमेशा विकास को रोकता है एवं गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। केंद्रीय बजट ने 20,670 करोड़ रु. का अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर लागू कर दिया।

3. केंद्रीय बजट 'काला धन पैदा करने वालों एवं रखने वालों' को सुरक्षा देगा एवं 'टैक्स चोरी करने वालों' को फायदा पहुंचाएगा। मोदी जी ने विदेशों से 80 लाख करोड़ रु. का काला धन वापस लाकर हर भारतीय के बैंक खाते में 15–20 लाख रु. जमा कराने का वायदा किया था। पिछले साल 2015–16 के बजट में विदेशों में जमा किए गए काले धन के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई थी। इससे 638 लोगों के द्वारा मात्र 3370 करोड़ रु. का ही खुलासा किया जा सका। यह हर भारतीय के खाते में मात्र 3. रु. जमा कराए जाने के बराबर है।

   केंद्रीय बजट 2016–17 में चार महीनों के लिए एमनेस्टी योजना के नाम पर कालाधनधारकों को उनके कालेधन को सफेद बनाने की सुविधा दी जा रही है। एक ईमानदार करदाता 30 प्रतिशत के कर के साथ 12 प्रतिशत का सरचार्ज, 2 प्रतिशत 'एजुकेशन कर' एवं 1 प्रतिशत का 'सेकंडरी एवं हायर एजुकेशन कर' अदा करता है। इसके विपरीत एक कालाधन धारक/टैक्स चोरी करने वाला केवल 30 प्रतिशत कर एवं 7.5 प्रतिशत सरचार्ज ही अदा करेगा। वो केवल 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त पेनल्टी ही अदा करेगा। इसके बदले में उसे जांच, सजा आदि से सुरक्षा मिल जाएगी एवं उससे इस पैसे का स्रोत तक नहीं पूछा जाएगा। क्या मोदी सरकार कालाधन रखने वालों को इसी तरह सजा देंगे? अंत में देखा जाए, तो नुकसान केवल आम करदाता का है।

4. केंद्र बजट 2016–17 में यह नहीं बताया गया कि वित्त मंत्री को उन सब खर्चों के लिए पूंजी कहां से मिलेगी, जिनकी वो घोषणा कर चुके हैं। 1.65 करोड़ रु. का नॉन–टैक्स राजस्व इकट्ठा हो जाने का अनुमान बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। 2015–16 में नॉन–टैक्स राजस्व 1 लाख करोड़ रु. था। इसलिए खर्च के बारे में की गई सभी घोषणाएं निराधार बातें हैं, जिनके लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई गई है।
5. बैंकिंग सेक्टर, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक गंभीर संकट में हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का दोबारा पूंजीकरण करने के लिए कम से कम 4,00,000 करोड़ रु. की जरूरत पड़ेगी। वित्तमंत्री ने बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के लिए केवल 25000 करोड़ रु. की घोषणा की है। इस गति से तो इस काम में 16 साल लग जाएंगे, जो काफी निराशाजनक है। 'बैंकिंग संकट' का हल निकाले बिना, अर्थव्यवस्था में कोई भी गति नहीं आ सकती है, न ही युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण हो सकता है और न ही निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट का डिस्बर्समेंट हो सकता है।